YEARLY ROUNDUP
2024-25

FRIENDS OF MSMEs
IN PARLIAMENT

वार्षिक सारांश
2024-25

FRIENDS OF MSMEs
IN PARLIAMENT

Shri Shankar Lalwani
(Chairman) and MP, Indore

"MSMEs are vital for India's 2047 development goal, as they drive job creation, innovation, and stronger supply chains. The forum- 'Friends of MSMEs in Parliament' can mentor these businesses. 'Friends of MSMEs in Parliament' is uniquely positioned to bridge the gap between parliamentary institutions and industry and shaping policies to remove regulatory impediments."

"MSMEs भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये केवल नौकरियाँ ही नहीं पैदा कर रहे, बल्कि नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। 'Friends of MSMEs in Parliament' समूह संसदीय संस्थानों और उद्योग के बीच सेतु का काम करके, MSMEs के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। यह नियामक बाधाओं को दूर करने वाली नीतियां बनाने में भी मदद करेगा।"

Shri Rajendra Agrawal
(Convenor) and Former MP, Meerut

"Government and large corporations alone can't generate the one crore annual jobs India needs. This massive employment can only be created if young people choose entrepreneurship and establish MSMEs. For this to happen, a robust ecosystem is crucial, providing ease of setting up, and essential support in finance, skills, and marketing."

सरकार और बड़े निगम अकेले ही भारत को हर वर्ष आवश्यक एक करोड़ नौकरियाँ पैदा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार तभी बन सकते हैं जब युवा उद्यमी बनने का विकल्प चुनें और MSMEs स्थापित करें। इसके लिए एक मजबूत अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण है, जो उद्यम स्थापित करने में सुगमता प्रदान करे और वित्त, कौशल और विपणन सहित कई क्षेत्रों में आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।

Background

The need for massive job creation cannot be over emphasized in case of India. But Governments are downsizing. And the large corporate sector is increasingly adopting capital intensive automized processes shredding workforce. The only way forward for creating jobs is through self-employment and creation of MSMEs. That is the only hope for millions of students graduating out of colleges also. However, both new and existing entrepreneurs face enormous challenges.

Almost all MPs, cutting across party lines, are sympathetic to their woes but have not been able to lend effective support to the MSME sector. There is a realization that MSMEs have not been able to leverage the Parliamentary system to clear their way to realize their maximum potential. A like-minded group of Members of Parliament -from both Lok Sabha and Rajya Sabha, have come forward to form a Group in the name of 'Friends of MSMEs in Parliament' to address the constraint and be a bridge between the MSMEs and the Parliament.

पृष्ठभूमि

भारत के संदर्भ में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकारें अपने आकार को घटा रही हैं और बड़ा कॉर्पोरेट क्षेत्र भी तेजी से पूंजी–प्रधान और स्वचालित प्रक्रियाएं अपना रहा है, जिससे कार्यबल कम होता जा रहा है। रोजगार सृजन का एकमात्र रास्ता स्वरोजगार और MSMEs के निर्माण के माध्यम से ही संभव है। यही करोड़ों छात्रों के लिए भी एकमात्र आशा है, जो प्रत्येक वर्ष कॉलेजों से स्नातक होकर निकलते हैं। यही प्रत्येक वर्ष कॉलेजों से स्नातक होकर निकलने वाले छात्रों के लिए एकमात्र आशा है।

हालांकि, नए और पहले से स्थापित दोनों ही उद्यमियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगभग सभी सांसद, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन MSME क्षेत्र को प्रभावी सहायता देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि MSMEs संसदीय व्यवस्था का उपयोग अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए नहीं कर पाए हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के समान विचारधारा वाले सांसदों के एक समूह ने फ्रेंड्स ऑफ MSMEs इन पार्लियामेंट नामक एक समूह बनाने के लिए पहल की है, ताकि इन बाधाओं को दूर किया जा सके और MSMEs और संसद के बीच एक सेतु का काम किया जा सके।

FRIENDS OF MSMEs
IN PARLIAMENT

Secretary: Rajeev Agarwal | **Mobile :** 9412221777 | **E-Mail :** secretary@friendsofmsme.org.in
Secretariat: FISME, B- 4/161 Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029, INDIA

Objectives

Ensuring Legislation incorporate MSME perspective

To interact with stakeholders, gather their concerns and aspirations and to voice them in the Parliament through a structured process during every Session of Parliament.

Leveraging Parliamentary Institutions for benefit of MSMEs

To leverage Parliamentary institutions such as Department related Parliamentary Standing Committees in resolving MSME issues.

Facilitating dialogue with Govt, institutions and MSMEs

To review efficacy of MSME related provisions of legislations & policies with MSME leaders and lend support for holding dialogue with respective Ministries/ Departments and institutions for improving outcomes for MSMEs.

उद्देश्य

विधायी प्रक्रियाओं में MSMEs का दृष्टिकोण शामिल करना सुनिश्चित करना

हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करना, उनकी चिंताओं और अपेक्षाओं को एकत्रित करना तथा प्रत्येक संसद सत्र के दौरान एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें संसद में प्रस्तुत करना।

MSME के हित में संसदीय संस्थाओं का उपयोग करना।

MSME से जुड़ी समस्याओं के समाधान में विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों जैसी संसदीय संस्थाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करना।

सरकार, संस्थाओं और MSME के साथ संवाद को सुगम बनाना।

कानूनों और नीतियों में शामिल MSME से संबंधित प्रावधानों की प्रभावशीलता की MSME नेताओं के साथ समीक्षा करना और MSME के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं के साथ संवाद स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना।

Year 2023-24 Review

SAMWAD: 'Dialogue with Parliamentarians'

Key Issues

Key issues discussed include challenges related to Access to Finance, such as banks' prepayment and foreclosure charges (ranging from 2-4%), restrictions posed by Third-Party Credit Ratings, and the demanding requirement of Bank Guarantees for MSMEs. The deliberations also covered Recommendations for the Election Manifesto 2024, various Indirect Tax Issues faced by MSMEs, and ensuring Access to Timely Payments for the sector.

Key Outcomes

Key outcomes included the conceptualization and operationalization of the 'Friends of MSMEs in Parliament' forum, alongside the establishment of a dedicated Banking Grievance Redressal Portal for MSMEs. Significant progress was made through representations to the Parliamentary Standing Committee on Finance and a meeting with the Hon'ble Minister of Finance. Furthermore, MSME - related recommendations were successfully incorporated into the Election Manifesto 2024. A notable event was the Seminar on Reducing Cost of Litigation, presided over by Shri Arjun Ram Meghwal.

वर्ष 2023–24 की समीक्षा

SAMWAD: सांसदों के साथ संवाद

चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे

चर्चा किए गए प्रमुख मुददों में वित्त तक पहुँचने से संबंधित चुनौतियाँ शामिल हैं, जैसे कि बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्री-पेमेंट और फोरक्लोजर शुल्क (2-4%), थर्ड पार्टी क्रेडिट रेटिंग द्वारा MSME की वित्त तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, और बैंक गारंटियों की अनिवार्य आवश्यकता। विचार–विमर्श में चुनाव घोषणापत्र 2024 के लिए सिफारिश MSME के सामने आने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दे, और इस क्षेत्र के लिए समय पर भुगतान तक पहुँच सुनिश्चित करना भी शामिल था।

मुख्य निष्कर्ष

प्रमुख परिणामों में 'Friends of MSMEs in Parliament' मंच की अवधारणा और संचालन, साथ ही MSME के लिए एक समर्पित बैंकिंग शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना शामिल है। संसदीय वित्त संबंधी स्थायी समिति को अभ्यावेदन और माननीय वित्त मंत्री के साथ बैठक के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके अलावा, MSME से संबंधित सिफारिशों को सफलतापूर्वक चुनाव घोषणापत्र 2024 में शामिल किया गया। एक उल्लेखनीय कार्यक्रम मुकदमेबाजी की लागत कम करने पर सेमिनार था, जिसकी अध्यक्षता श्री अर्जुन राम मेघवाल ने की।

Seminars and Roundtables

सेमिनार और गोलमेज चर्चाएँ

On August 10, 2023, a seminar titled 'Reducing Cost of Litigation for MSMEs' was held in New Delhi, Presided over by the Hon'ble Minister of Law & Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, the event addressed key issues such as the high cost of litigation and its impact on GDP, challenges with ADR including award execution, the effectiveness of the IBC Code and its harmonization with the MSMED Act, the Mediation Act's role in resolving commercial disputes.

10 अगस्त, 2023 को, माननीय कानून और न्याय मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में MSMEs के लिए मुकदमेबाजी की लागत कम करना विषय पर एक सेमिनार की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में मुकदमेबाजी की उच्च लागत, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की चुनौतियाँ, IBC की MSMED act के साथ प्रभावशीलता, और वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता अधिनियम की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

The roundtable focused on the Indirect Tax challenges faced by MSMEs, highlighting the critical need for a simplified tax regime to empower the sector. Key issues raised included GST-related complexities, such as the difficulty of securing Principal Place of Business registrations in every state of operation and updating GST certificates for additional premises.

यह बैठक MSME के सामने आने वाली अप्रत्यक्ष कर चुनौतियों पर केंद्रित थी, जिसमें इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक सरलीकृत कर व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया। उठाए गए प्रमुख मुद्दों में GST से संबंधित जटिलताएँ शामिल थीं, जैसे कि संचालन के प्रत्येक राज्य में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पंजीकरण प्राप्त करने में कठिनाई और अतिरिक्त परिसरों के लिए GST प्रमाणपत्र।

Seminars and Roundtables

सेमिनार और गोलमेज चर्चाएँ

A comprehensive study aimed at quadrupling Meerut's GDP was released by Shri Pankaj Chaudhary, Hon'ble Union Minister of State (Finance); Shri Rajendra Agrawal, Convenor of Friends of MSMEs in Parliament and Former MP from Meerut; and Shri Harikant Ahluwalia, Mayor of Meerut. This study's findings have since been disseminated to key policymakers, including NITI Aayog, the Prime Minister's Office (PMO), the Chief Minister's Office (CMO), DPIIT, and the Ministry of MSME

मेरठ के GDP को चार गुना करने के उद्देश्य से एक व्यापक अध्ययन श्री पंकज चौधरी, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, श्री राजेंद्र अग्रवाल, 'Friends of MSMEs in Parliament' के संयोजक और मेरठ के पूर्व सांसद, तथा श्री हरिकांत अहलूवालिया, मेरठ के महापौर द्वारा जारी किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों को तब से नीति आयोग, PMO, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), DPIIT और MSME मंत्रालय सहित प्रमुख नीति निर्माताओं तक पहुँचाया गया है।

Dialogue With IIT Madras on Startups and Enhancing Export Competitiveness

A dialogue took place in New Delhi. This event brought together members of 'Friends of MSMEs in Parliament,' FISME office bearers, and a delegation of 80 students and research scholars from IIT Madras's Public Policy Club. The discussion spanned various critical issues for MSMEs, including business challenges and opportunities, start-up collaboration, and the growth of the textile industry.

IIT मद्रास के साथ स्टार्टअप और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर संवादः इस कार्यक्रम में Friends of MSME in Parliament के सदस्य, FISME के पदाधिकारी और IIT मद्रास के पब्लिक पॉलिसी क्लब के 80 छात्रों व शोधार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इस चर्चा में MSME के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे, जिनमें व्यावसायिक चुनौतियाँ और अवसर, स्टार्टअप– MSME सहयोग और कपड़ा उद्योग के विकास जैसे विषय प्रमुख थे।

Representation to Government

सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व

A delegation from FISME, led by Shri Rajendra Agarwal, Convenor of 'Friends of MSMEs in Parliament,' met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to advocate for the prioritization of medium-sized enterprises in economic policy. Separately, the Convenor arranged a meeting with Shri Jayant Sinha, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Finance, highlighting major issues such as bank foreclosure and prepayment charges, and challenges with Bank Loan Ratings (BLR) and Bank Guarantees (BGs) in accessing finance.

FISME के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसकी अगुवाई 'Friends of MSME in Parliament' के संयोजक श्री राजेंद्र अग्रवाल ने की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आर्थिक नीति निर्माण में मध्यम आकार के उद्यमों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त संयोजक ने संसदीय वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जयंत सिन्हा के साथ एक बैठक की व्यवस्था की जिसमें बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले फोरक्लोजर और प्रीपेमेंट शुल्क तथा वित्त तक पहुँचने में BLR और BGs से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को उजागर किया गया।

MSMEs Aspirations for Election Manifesto 2024 suggested by the Forum:

i) Legalizing remote work/work from households for self-employed, ii) Reforming insolvency regulations, iii) Simplifying compliances and laws, iv) Reducing cost of contractual litigation for MSMEs, v) Reviving Manufacturing through technological upgradation of MSMEs

वर्ष 2024 के चुनाव घोषणा पत्र के लिए अपेक्षाएँ:

i) स्वरोजगार करने वालों के लिए घर से कार्य करने को कानूनी मान्यता देना, ii) अनुपालन प्रक्रियाओं और कानूनों को सरल बनाना। iii) इन्सॉल्वेंसी नियमों में सुधार करना। MSME के लिए संविदात्मक मुकदमों की लागत को कम करना। iv) MSME के तकनीकी उन्नयन के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना, v) MSME के लिए वित्त तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।

5th SAMWAD

5वाँ संवाद

5th SAMWAD

Practice of holding SAMWAD dialogues between industry representatives and Parliamentarians continued in 2024-25 as well. On August 7, 2024, the 'Friends of MSMEs in Parliament' forum, with facilitation from FISME, organized its 5th SAMWAD dialogue in New Delhi. This important event saw participation from Members of Parliament across various parties.

During the dialogue, Chairman Shri Shankar Lalwani underscored the crucial role of MSMEs in helping India achieve its ambitious goal of becoming a developed nation by 2047. Convenor Shri Rajendra Agrawal highlighted the forum's success in bridging the gap between industry and policymakers, fostering mutual understanding, and pinpointing effective solutions. Industry representatives present at the dialogue further emphasized the need to concentrate on growth drivers and the specific requirements of MSMEs.

उद्योग प्रतिनिधियों और सांसदों के बीच संवाद (SAMWAD) वार्ताओं का अभ्यास 2024–25 में भी जारी रहा। 7 अगस्त, 2024 को, FISME के सहयोग से 'Friends of MSMEs in Parliament' मंच ने नई दिल्ली में अपना पांचवां संवाद (SAMWAD) कार्यक्रम आयोजित किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया।

संवाद के दौरान, अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। संयोजक श्री राजेंद्र अग्रवाल ने उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच की खाई को पाटने, आपसी समझ को बढ़ावा देने और प्रभावी समाधानों की पहचान करने में मंच की सफलता पर प्रकाश डाला। संवाद में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों ने आगे विकास के प्रेरकों और MSMEs की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

6th SAMWAD

6वाँ संवाद

6th SAMWAD

The 6th SAMWAD dialogue, organized by 'Friends of MSMEs in Parliament' and facilitated by FISME, was held on November 27, 2024, in New Delhi. The discussions focused on the challenges MSMEs face in accessing credit from banks and navigating regulatory hurdles. Key concerns included SMA provisions, delayed payments, and issues related to the arbitration process. Parliamentarians highlighted the urgent need to revive the manufacturing sector and promote self-employment. It was proposed that the 'Friends of MSMEs in Parliament' forum take on a mentorship role to support MSMEs, along with the establishment of a dedicated committee to address banking, finance, and regulatory challenges.

27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में 'Friends of MSMEs in Parliament' द्वारा आयोजित और FISME द्वारा संचालित 6वां संवाद (SAMWAD) कार्यक्रम संपन्न हुआ। चर्चा का केंद्र बिंदु MSME को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों और अन्य नियामकीय अड़चनों पर रहा। कार्यक्रम में SMA प्रावधानों, भुगतान में देरी और मध्यस्थता प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं पर विशेष चिंता जताई गई। सांसदों ने विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। MSME के समर्थन हेतु 'Friends of MSMEs in Parliament' मंच को मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का सुझाव दिया गया, साथ ही बैंकिंग, वित्तीय और नियामकीय चुनौतियों के समाधान के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया।

7th SAMWAD

The 7th SAMWAD dialogue, organized by 'Friends of MSMEs in Parliament' and facilitated by FISME, took place on February 6, 2025, in New Delhi. The central focus of the discussion was a critical review of labour laws, aiming to strike a delicate balance between enhancing MSME export competitiveness and safeguarding workers' welfare. The dialogue also addressed the challenges inherent in the current import policy.

Concerns were specifically raised regarding the impact of anti-dumping and safeguard duties on raw materials, which inadvertently make Indian MSMEs less competitive. This is further exacerbated by a policy that seemingly encourages finished goods imports, often benefiting larger companies. To address these complex issues and find equitable solutions, a roundtable discussion was proposed, bringing together key industries and associations from vital sectors such as steel, chemicals, and textiles.

7वाँ संवाद

Friends of MSMEs in Parliament द्वारा आयोजित और FISME द्वारा सुगम बनाया गया 7वाँ संवाद कार्यक्रम 6 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में हुआ। इस चर्चा का मुख्य केंद्र श्रम कानूनों की गहन समीक्षा थी, जिसका उद्देश्य MSME निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करना था। संवाद में वर्तमान आयात नीति में निहित चुनौतियों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसमें कच्चे माल पर लगाए गए एंटी–डंपिंग और सुरक्षा शुल्क के प्रभाव के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, क्योंकि ये भारतीय MSMEs को अनजाने में कम प्रतिस्पर्धी बना देते हैं। यह स्थिति उस नीति से और भी जटिल हो जाती है जो तैयार माल के आयात को बढ़ावा देती हुई प्रतीत होती है, जिससे अक्सर बड़ी कंपनियों को लाभ होता है। इन जटिल मुद्दों को संबोधित करने और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए, स्टील, रसायन और वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगों और संघों को एक साथ लाने वाली एक गोलमेज चर्चा का प्रस्ताव किया गया।

8th SAMWAD

The 8th SAMWAD dialogue, organized by 'Friends of MSMEs in Parliament' and facilitated by FISME, took place in March 2025 in New Delhi. Formal presentation of recommendations stemming from the earlier Roundtable discussion was made, which aimed to balance the often-conflicting interests of large raw material producers and MSMEs. A notable suggestion was the inclusion of FISME in ministerial discussions concerning the Jan Vishwas Bill. The dialogue involved a crucial discussion around a memorandum intended for the Parliamentary Standing Committee on Finance. This memorandum addressed a range of pressing concerns for MSMEs, such as the intricacies of SMA framework, issues related to Bank Loan Ratings (BLR), challenges in bank grievance redressal mechanisms, and the contentious nature of charges on loan prepayment or foreclosure.

8वाँ संवाद

'Friends of MSMEs in Parliament' द्वारा आयोजित और FISME द्वारा सुगम बनाया गया 8वाँ संवाद (SAMWAD) कार्यक्रम मार्च 2025 में नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में पिछली गोलमेज चर्चा से निकली सिफारिशों का औपचारिक प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े कच्चे माल उत्पादकों और MSMEs के अक्सर परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना था। एक उल्लेखनीय सुझाव जन विश्वास विधेयक से संबंधित मंत्रिस्तरीय चर्चाओं में FISME को शामिल करना था। संवाद में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के लिए तैयार किए गए एक ज्ञापन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस ज्ञापन में MSMEs के लिए कई ज्वलंत चिंताओं को संबोधित किया गया, जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA) फ्रेमवर्क की जटिलताएँ, बैंक ऋण रेटिंग (BLR) से संबंधित मुद्दे, बैंक शिकायत निवारण तंत्र में चुनौतियाँ, और ऋण के पूर्व भुगतान या फोरक्लोजर पर लगने वाले शुल्कों की विवादास्पद प्रकृति।

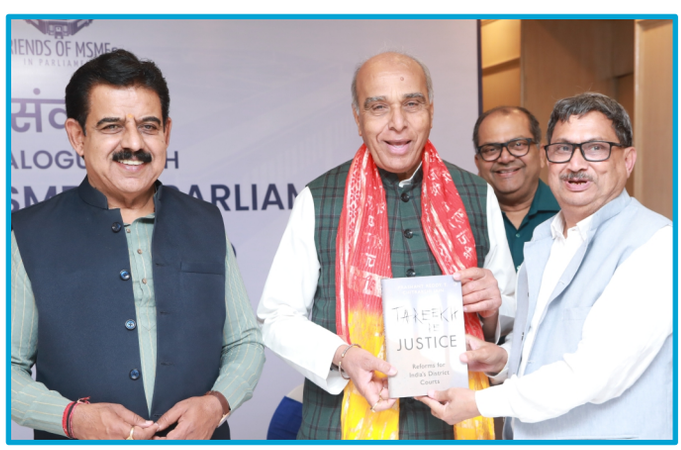

Workshop on Strategic Partnership & Business Opportunities for SMEs

On August 30, 2024, IFCI, a Government of India undertaking, in collaboration with FISME—the secretariat for 'Friends of MSMEs in Parliament'—jointly conducted a workshop in New Delhi. The workshop served as an outreach initiative for the Centre of Excellence for Aspiring SMEs. Shri Rajendra Agrawal, Convenor of the forum, delivered the valedictory address at the program.

Shri Rajendra Agrawal also led a delegation of industry representatives to meet the Hon'ble Minister of Finance, where the idea of establishing such a dedicated centre for SMEs was proposed and well-received. Inputs and suggestions from members of 'Friends of MSMEs in Parliament' played a valuable role in the conceptualization of the Centre of Excellence for Aspiring SMEs.

SME के लिए रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक अवसरों पर कार्यशाला

30 अगस्त, 2024 को, भारत सरकार के एक उपक्रम IFCI ने FISME के सहयोग से नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला 'Centre of Excellence for Aspiring SMEs' के लिए एक आउटरीच पहल के रूप में आयोजित की गई। मंच के संयोजक श्री राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम में समापन भाषण दिया। इससे पहले, श्री राजेंद्र अग्रवाल ने उद्योग प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए माननीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी, जहाँ SMEs के लिए ऐसे समर्पित केंद्र की स्थापना का विचार प्रस्तावित किया गया था और इसे खूब सराहा गया। Friends of MSMEs in Parliament के सदस्यों से प्राप्त इनपुट और सुझावों ने 'Centre of Excellence for Aspiring SMEs' की अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

National Roundtable of MSMEs' Access to Finance & Timely Payments

FISME, the secretariat for 'Friends of MSMEs in Parliament', in collaboration with the Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME), jointly organized a National Roundtable on September 28, 2024, in New Delhi. The Roundtable was presided over by Shri S.C.L. Das, Secretary, Ministry of MSME, Government of India. The discussions focused on key challenges faced by MSMEs, particularly issues related to access to formal credit and delays in payments.

Deliberations with members of 'Friends of MSMEs in Parliament' were instrumental in shaping the issues presented at the National Roundtable. Key concerns like the SMA framework, bank grievance redressal, Bank Loan Rating (BLR) were later shared with the Parliamentary Standing Committee on Finance and other forums.

MSME के वित्तीय पहुंच और समय पर भुगतान पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

FISME, जो 'Friends of MSMEs in Parliament' का सचिवालय है, ने ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्यो-रशिप (GAME) के सहयोग से 28 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस गोलमेज की अध्यक्षता भारत सरकार के MSME मंत्रालय के सचिव श्री एस.सी.एल. दास ने की। चर्चाएँ MSME द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों, विशेष रूप से औपचारिक ऋण तक पहुँच और भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थीं।

'Friends of MSMEs in Parliament' के सदस्यों के साथ विचार विमर्श राष्ट्रीय गोलमेज में प्रस्तुत किए गए मुद्दों को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। SMA (स्पेशल मेंशन अकाउंट) फ्रेमवर्क, बैंक शिकायत निवारण और BLR (बैंक लोन रेटिंग) जैसी प्रमुख चिंताओं को बाद में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति और अन्य मंचों के साथ साझा किया गया।

International Conference

FISME, the secretariat for 'Friends of MSMEs in Parliament', organized an International Conference on 'Strategies for Mass Scale Technological Upgradation for MSMEs: Global Experiences and Lessons for India' on 7th March 2025. Chief Guest, Shri Rajendra Agrawal, Convenor of Friends of MSMEs in Parliament addressed the gathering and emphasized the importance of policy interventions to support technology adoption by MSMEs.

The conference shared international insights on cluster-level technological upgrades, including success stories from France, Germany, Japan, Spain. Conference emphasized importance of international collaboration and knowledge sharing in developing effective strategies for Indian context. Technology, skilling, and financing should be considered together rather than in isolation and policies should support an organic growth of clusters driven by market forces.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

FISME, जो 'Friends of MSMEs in Parliament' का सचिवालय है, ने 7 मार्च, 2025 को 'MSMEs के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी उन्नयन हेतु रणनीतियाँः वैश्विक अनुभव' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि, श्री राजेंद्र अग्रवाल ने सभा को संबोधित किया और MSMEs द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में क्लस्टर–स्तरीय तकनीकी उन्नयन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्दृष्टि साझा की गई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन जैसे देशों की सफलता की कहानियाँ शामिल थीं। सम्मेलन ने भारतीय संदर्भ के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझाकरण के महत्व पर बल दिया। यह भी जोर दिया गया कि प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और वित्तपोषण को अलग–अलग देखने के बजाय एक साथ विचार किया जाना चाहिए, और नीतियों को बाजार की ताकतों द्वारा संचालित क्लस्टरों के एक व्यवस्थित विकास का समर्थन करना चाहिए।

Roundtable Discussion

A critical review of India's import policy is essential due to its bias against raw material imports and in favor of finished goods, predominantly benefiting large corporations. This issue, first highlighted in the 7th SAMWAD, led to a roundtable on March 26, 2025, convened by 'Friends of MSMEs in Parliament' and facilitated by FISME. Key takeaways revealed that anti-dumping duties on raw materials disproportionately harm MSMEs by increasing input costs and reducing export competitiveness, even as global raw material prices fall. This also negatively impacts large manufacturers relying on MSME supply chains. Therefore, a policy review is recommended to balance the interests of MSMEs and large raw material producers, emphasizing detailed sub-sector analysis, establishing mutually recognized certification agencies, and creating an MSME import helpdesk. Securing the domestic supply chain amid global uncertainties is crucial.

गोलमेज चर्चा

भारत की आयात नीति की गहन समीक्षा आवश्यक है क्योंकि यह कच्चे माल के आयात के प्रति पक्षपाती है और तैयार माल के आयात के पक्ष में है, जिससे मुख्य रूप से बड़े निगमों को लाभ होता है। यह मुद्दा, जिसे पहली बार 7वें SAMWAD में उठाया गया था। मुख्य निष्कर्षों से पता चला कि कच्चे माल के आयात पर एंटी–डंपिंग शुल्क MSMEs को इनपुट लागत बढ़ाकर और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करके असम्मानजनक रूप से नुकसान पहुँचाते हैं, भले ही वैश्विक कच्चे माल की कीमतें गिर रही हों। यह MSME आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर बड़े निर्माताओं को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। MSMEs और बड़े कच्चे माल उत्पादकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक नीति समीक्षा की सिफारिश की जाती है, जिसमें विस्तृत उप–क्षेत्र विश्लेषण, पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों की स्थापना और एक MSME आयात हेल्पडेस्क का निर्माण शामिल है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना भी महत्वपूर्ण है।

Discussion on US Reciprocal Tariff

India's exports to the U.S. reached $77.5 billion in FY24, with Indian MSMEs contributing nearly half, particularly in sectors like textiles, engineering, pharmaceuticals, and gems & jewellery. To understand the impact of reciprocal tariffs, 'Friends of MSMEs in Parliament' hosted a roundtable with experts in New Delhi. The discussion concluded that reciprocal tariffs are not WTO-friendly or sustainable long-term, though they offer a chance to restructure India's economy. Bilateral Trade Agreements (BTA) are seen as a viable solution. Recommendations include balancing reciprocal tariffs with BTA concessions, ensuring BTAs have a sunset clause (preferably till 2039) & retractable concessions, and creating a platform to address MSME concerns and tariff impacts in the U.S. market. Beyond tariffs, India should also address non-tariff issues like fair access to government procurement for U.S. firms and their IP concerns.

अमेरिकी प्रतिशोधात्मक शुल्क पर चर्चा

वित्त वर्ष 2024 में भारत का अमेरिका को निर्यात $77.5 बिलियन तक पहुँच गया, जिसमें भारतीय MSMEs का लगभग आधा योगदान रहा, खासकर कपड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और रत्न व आभूषण जैसे क्षेत्रों में। पारस्परिक शुल्कों के प्रभाव को समझने के लिए फोरम ने नई दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की मेजबानी की। चर्चा में यह निष्कर्ष निकला कि पारस्परिक शुल्क WTO के अनुकूल नहीं हैं हालांकि वे भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का अवसर प्रदान करते हैं। BTAs को एक व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा जा रहा है। सिफारिशों में पारस्परिक शुल्कों को BTA रियायतों के साथ संतुलित करना, यह सुनिश्चित करना कि BTAs में एक सनसेट क्लॉज और प्रतिवर्ती रियायतें हों, तथा अमेरिकी बाजार में MSME चिंताओं और शुल्क प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक मंच बनाना शामिल है। भारत को अमेरिकी फर्मों के लिए सरकारी खरीद तक उचित पहुंच और उनके IP संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करना चाहिए।

Representations and Submissions

प्रतिनिधित्व और प्रस्तुतियाँ

Parliamentary Standing Committee on Finance:

Key issues presented included- i) 'Need for a comprehensive review of the policy answering key questions, ii) A new rating mechanism for unlisted companies up to the turnover of Rs 1000 Crore, based on short-term 'solvency' and not on 'Return on Investment'. Iii) Grievance redressal mechanism for MSME borrowers and adherence to Code of Bank's Commitment to MSMEs by banks and NBFCs, iv) Institutions such as 'Friends of MSMEs in Parliament may be made part of a Centralized Grievance Redressal.

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी सविवि को अभ्यर्दिनः

i) नीति की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता, जो प्रमुख प्रश्नों का उत्तर दे। ii) रु 1000 करोड़ तक के टर्नओवर वाली असूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक नई रेटिंग प्रणाली, जो अल्पकालिक 'शोधन क्षमता' पर आधारित हो, न कि 'निवेश पर प्रतिफल' पर। iii) MSME उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र और बैंकों व NBFCs द्वारा MSMEs के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता का पालन। iv) Friends of MSMEs in Parliament जैसे संस्थानों को एक केंद्रीत शिकायत निवारण तंत्र का हिस्सा बनाया जाए।

Select Committee of Lok Sabha to Examine the Income Tax Bill 2025:

Memorandum for ease of doing business by de-criminalizing laws. Key issues presented: i) Economic Double Taxation, ii) Long Term Capital Gain Tax imposed on industry iii) Liability of Partner at the time of dissolution, iv) Issue of Liability of partners of limited liability partnership in liquidation, v) Rigorous punishments should be substituted by penalties

आयकर विधेयक 2025 की जांच करने के लिए लोकसभा की प्रवर समितिः

प्रस्तुत किए गए प्रमुख मुद्देः i) आर्थिक दोहरा कराधान, ii) उद्योग पर लगाया गया दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, iii) फर्म के विघटन के समय साझेदार की देयता, iv) परिसमापन में सीमित देयता भागीदारी के साझेदारों की देयता का मुद्दा, v) कठोर दंडों को उचित शास्तियों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

RBI's Standing Advisory Committee to Review Flow of Credit to MSMEs:

FISME represented MSME concerns to the RBI in Ahmedabad, focusing on improving credit flow, enhancing the TReDS ecosystem, and incentivizing restructuring of stressed MSME loans

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थायी सलाहकार समिति

FISME ने अहमदाबाद में RBI के समक्ष MSME की चिंताओं को प्रस्तुत किया। इन चिंताओं में मुख्य रूप से ऋण प्रवाह में सुधार, TReDS इकोसिस्टम को बेहतर बनाना और तनावग्रस्त MSME ऋणों के पुनर्गठन को प्रोत्साहित करना शामिल था।

Impact of Work

कार्य का प्रभाव

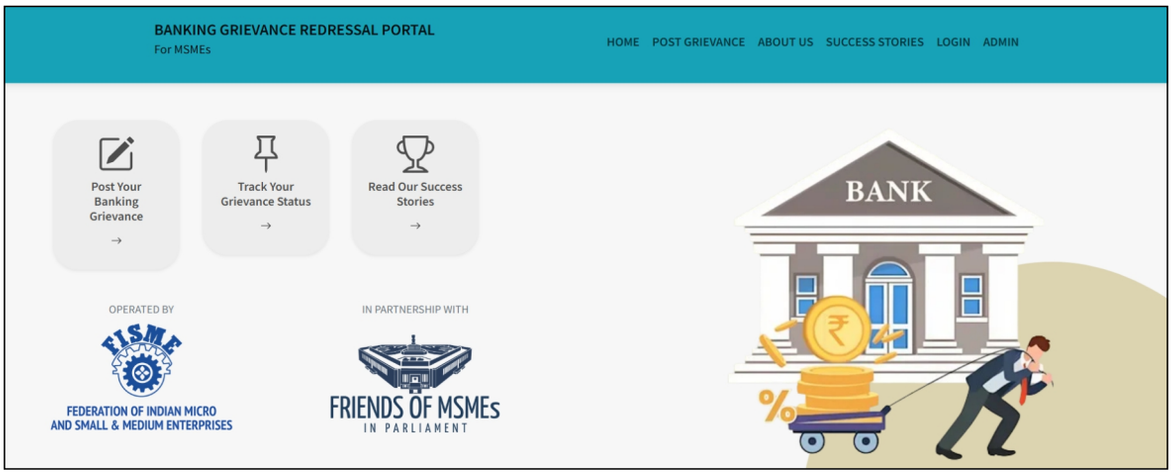

https://bankgrievances.com/

The 'Friends of MSMEs in Parliament' has emerged as a well-respected, bipartisan forum, influencing ministries, parliamentary bodies, and standing committees through its credible recommendations. Their deliberations, particularly during SAMWAD, provide valuable input for the Budget, legislation, and policy. Notable impacts include Budget announcements for sick industrial units and alternative loan rating mechanisms, SIDBI's direct lending to MSMEs, and a revised MSME classification.

The forum's suggestions also influenced the 2024 election manifesto. Furthermore, they launched an online platform on December 14, 2023, for MSME banking grievances, and have contributed to significant studies which were disseminated to Ministries, PMO, and NITI Aayog. Several important studies are also expected to be released in the coming year.

'Friends of MSMEs in Parliament' एक सुप्रतिष्ठित, द्विदलीय मंच के रूप में उभरा है। यह अपनी विश्वसनीय सिफारिशों के माध्यम से मंत्रालयों, संसदीय निकायों और स्थायी समितियों को प्रभावित करता है। मंच की चर्चाएँ, विशेषकर संवाद (SAMWAD) के दौरान बजट, कानून और नीति के लिए बहुमूल्य सुझाव प्रदान करती हैं। इसके उल्लेखनीय प्रभावों में बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिए बजट घोषणाएँ और वैकल्पिक ऋण रेटिंग तंत्र, SIDBI द्वारा MSMEs को सीधा ऋण तथा एक संशोधित MSME वर्गीकरण शामिल हैं।

मंच के सुझावों ने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र को भी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 14 दिसंबर, 2023 को MSME बैंकिंग शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है। मंच ने महत्वपूर्ण अध्ययनों में भी योगदान दिया है, जिन्हें मंत्रालयों, PMO और नीति आयोग तक पहुँचाया गया है।

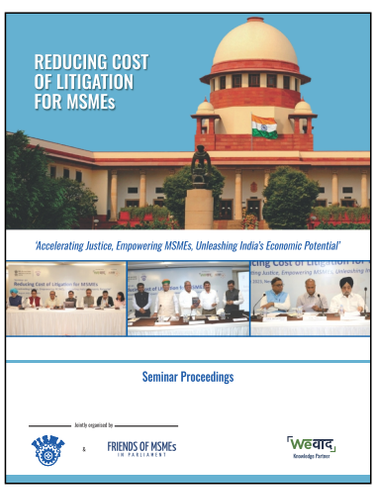

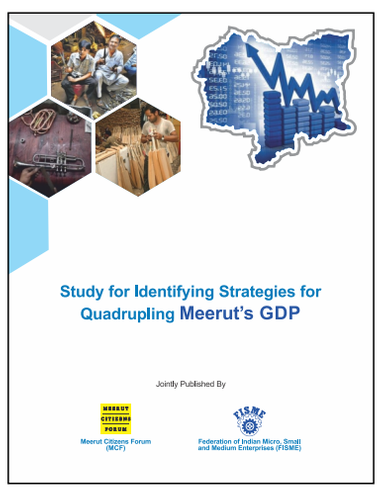

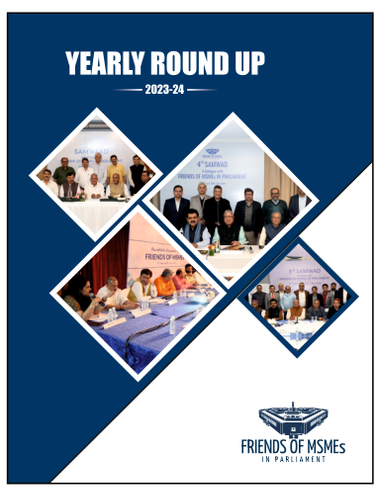

Participating MPs- 17th and 18th Lok Sabha

Name & Constituency		Name & Constituency	
Shri Shankar Lalwani Indore, Madhya Pradesh **Chairman**		**Shri Rajendra Agrawal** Meerut, Uttar Pradesh Convenor	
Smt. Priyanka Jarkiholi Chikkodi, Karnataka		**Dr. Ganapathy P Rajkumar** Coimbatore, Tamil Nadu	
Shri Jagdambika Pal Domariyaganj, Uttar Pradesh		**Shri Golla Babu Rao** Member Rajya Sabha, Payakaraopet, Andhra Pradesh	
Shri Jugal Kishore Jammu		**Shri Mukesh Kumar Chandrakant** Surat, Gujarat	
Shri Radhakrishna Gulbarga, Karnataka		**Shri Ramesh Awasthi** Kanpur, Uttar Pradesh	
Shri Sudhir Gupta Mandaur, Madhya Pradesh		**Shri CP Joshi** Chittorgarh, Rajasthan	
Shri Mitesh Patel Anand, Gujarat		**Shri Parbhubhai Vasava** Bardoli, Gujarat	
Shri Alok Sharma Bhopal, Madhya Pradesh		**Shri Ashish Dubey** Jabalpur, Madhya Pradesh	
Shri Kripanath Mallah Karimganj, Assam			

Inspirational Voices

प्रेरणादायक आवाजें

"The forum has enabled MSMEs to contribute to the parliamentary system in more effective manner. Representations made at parliamentary forums have brought to light several key MSME issues. The import policy is one such issue, which needs to be comprehensively examined to align the interests of both MSMEs and large companies."

Shri Jagdambika Pal
Domariyaganj (UP)

''यह मंच MSMEs को संसदीय प्रणाली में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बना पाया है। संसदीय मंचों पर दिए गए प्रस्तुतीकरणों ने MSME से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों को सामने लाया है। आयात नीति ऐसा ही एक मुद्दा है जिसकी व्यापक रूप से जांच करने की आवश्यकता है ताकि MSMEs और बड़ी कंपनियों दोनों के हितों को एक साथ साधा जा सके।"

"The government has prioritized revitalizing the MSME sector and fostering self-employment. Concurrently, bankers and financial institutions ought to focus on creating financial products that specifically cultivate employers and entrepreneurs."

Shri Jugal Kishore
Jammu

"सरकार ने MSMEs क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही बैंकरों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे वित्तीय उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विशेष रूप से नियोक्ताओं और उद्यमियों को तैयार करें।"

"Need for a forum like this is felt both inside and outside of parliament. This government through its commitment over the last decade has demonstrated its willingness to listen and resolve the concerns of MSMEs. The forum should presume guardianship and mentorship role for MSMEs."

Shri Sudhir Gupta
Mandaur,
Madhya Pradesh

"संसद के अंदर और बाहर ऐसे एक मंच की आवश्यकता महसूस की जाती है। इस सरकार ने पिछले एक दशक में अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से MSMEs की चिंताओं को सुनने और हल करने की अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है। इस मंच को MSMEs के लिए एक संरक्षक और परामर्शदाता की भूमिका निभानी चाहिए।"

"The 45 days payment limit was brought with the intention to secure timely payments for MSMEs. But the provision has had an adverse effect. It has discouraged large companies to procure from MSME suppliers."

Shri Mukesh Kumar Chandrakaant
Surat, Gujarat

"45–दिन की भुगतान सीमा MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के इरादे से लाई गई थी। हालाँकि, इस प्रावधान का विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसने बड़ी कंपनियों को MSME आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी करने से हतोत्साहित किया है।"

Chairman

Shri Shankar Lalwani, a VJTI Mumbai alumnus, is a three-time Lok Sabha MP for Indore, currently serving on the Committee on Housing and Urban Affairs. He has also been a member of other significant committees, including Public Undertakings and Culture and Tourism. Prior to his parliamentary career, he held key leadership roles as Councillor and Chairman of the Indore Municipal Corporation and Indore Development Authority. Lalwani's dedication to urban development has profoundly shaped Indore's landscape. He has been recognized for spearheading Indore's cleanliness initiatives. His journey reflects a strong commitment to public service and grassroots progress.

अध्यक्ष

श्री शंकर लालवानी, वीजेटीआई मुंबई के पूर्व छात्र हैं और इंदौर से लगातार तीन बार के लोकसभा सांसद हैं। वर्तमान में वे आवास और शहरी मामलों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। अपने संसदीय करियर के दौरान, वे सार्वजनिक उपक्रम और संस्कृति एवं पर्यटन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं। संसद सदस्य बनने से पहले, उन्होंने इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण में पार्षद और अध्यक्ष जैसे प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया। इंदौर के स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए उन्हें विशेष पहचान मिली है। उनका यह सफर जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Convenor

Mr. Rajendra Agrawal has been elected as a Member of Parliament from the Meerut-Hapur Lok Sabha constituency in Uttar Pradesh continuously since 2009, serving three terms. He holds a master's degree in Physical Science. During his parliamentary tenure, he has served as the Chairperson of the Lok Sabha Committee on Government Assurances and also chaired important committees such as the Joint Parliamentary Committee on the Citizenship (Amendment) Bill 2016 and the Joint Parliamentary Committee on the Forest (Conservation) Amendment Bill 2023.

संयोजक

श्री राजेंद्र अग्रवाल उत्तर प्रदेश की मेरठ–हापुड़ लोकसभा सीट से वर्ष 2009 से लगातार तीन बार संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान वह लोकसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति तथा नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति एवं वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति जैसी महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के भी सभापति रहे हैं। वह लोकसभा के सभापति पैनल के सदस्य रहने के साथ ही अन्य विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे हैं।

Note / नोट

Note / नोट

Note / नोट

FRIENDS OF MSMEs IN PARLIAMENT

Secretariat: FISME, B- 4/161, Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029, INDIA
Phone: +91 -11 - 48460000, 46018592 | **Mobile:** +91-9013180336
E-Mail: secretary@friendsofmsme.org.in